

200 Years of Indian Origin Tamils in Sri Lanka

Indian Origin Tamils (IOT) of Sri Lanka are Tamil people of Indian origin, also known as Malayaga Tamilar, who predominantly descend from workers sent from Tamil Nadu to Sri Lanka in the 19th & 20th centuries to work in coffee, tea and rubber plantations. They are instrumental in the development of the plantation sector. These Tamil-speaking people mostly live in the central highlands, also known as the Malayagam or Hill country.

The first group of Indian Origin Tamils (IOT) arrived in Sri Lanka, then called Ceylon, in 1823 as labourers to work in coffee and then tea, rubber, and cocoa plantations in the hilly regions of Sri Lanka. Later in the 1900s, substantial numbers of Tamils from India also came to settle in Ceylon as financial entrepreneurs and grocers. They were the trading community of IOT, which was not part of the plantation economy and who had come to Ceylon since then. After the British takeover of the administration of Sri Lanka (then known as Ceylon) in the early 19th Century, they involved themselves in various activities, including economic enterprises such as plantation and agriculture.

The Indian Origin Tamils were put through immense hardship during the British rule in India and Sri Lanka. During the 1830s, Indian Origin Tamils working in coffee estates were not provided with wages. Instead, they were asked to trade coffee beans gathered by them for commodities from shops. Only after 100 years of immigration to Sri Lanka did the Indian Origin Tamils' hardships become known to the international community.

The Indian Tamils in Sri Lanka were enumerated as a separate ethnic group for the first time in the census of 1911 when the people of this community became the second-largest ethnic group in Sri Lanka. The government considered them a separate group and named them "Indian Tamils" in the official census from that year onwards. For various administrative and political purposes, the government officially identified the community as "Indian Tamils".

In the 1940s, the trade union movement had galvanised the plantation workers into a militant working class. They joined hands with the Lanka Sama Samaja (or Socialist) Party (LSSP), which carried the message of a working-class struggle for liberation from exploitation by mostly British plantation companies. The Ceylon Citizenship Act of 1948 made the IOT community stateless.

As they had no means of electing anyone to the Parliament, they ceased to be a concern to the Sri Lankan Parliament. The plantation workers were thus forgotten from 1948 to 1964. They were unable to profit from any progressive legislation. The housing, health and education of the plantation workers were neglected.

A Satyagraha campaign was launched to protest the deprivation of representation by the Indian Tamil leaders in 1952 by the CWC

led by Soumyamoorthy Thondaman, Abdul Aziz, G.K. Motha, and P. Perisundaram, K. Rasalingham, C.R. Motha, Kottampalli Govindan Sellappa Nayar, Vaithiyalingham Palanisami Pillai and many others participated in this struggle. It occurred at the Galle Face Green, in front of Ceylon's parliament.

After making the IOT community stateless, Citizenship rights granted according to eligibility criteria set out in a few enactments enabled Indian Tamils to become part of the country's permanent population. This was a long process. There was much political manoeuvring by the Indian Tamil leaders and the regimes in power at various times to solve problems. Also, the process imposed on the Indian-origin Tamils a price which they paid through heavy sacrifices and financial hardships. After two generations or more of Indian Tamils after the Independence of Sri Lanka, the final batch of the 300,000 stateless IOT population was granted citizenship in 2003 by a Bill proposed to the Sri Lankan Parliament by Arumugam Thondaman. The IOTs suffered the agony of being a stateless community. Accordingly, the Indian Tamil population in Sri Lanka experienced different issues and trends during the last two hundred years of their stay.

The current political regime in India followed a proactive approach to address the issue of IOT. Prime Minister Narendra Modi visited central Sri Lanka in May 2017, where Indian Origin Tamils were settled and inaugurated various projects completed with the aid of the Government of India. This includes the completion of 4,000 concrete houses for the Indian Origin Tamils and the announcement of 10,000 new houses.

During the visit of Sri Lankan President Ranil Wickremesinghe to India on 21st July 2023, Prime Minister Narendra Modi announced the implementation of various projects worth Rs 75 crore for Indian-origin Tamil citizens of Sri Lanka while celebrating the 75th anniversary of diplomatic relations with Sri Lanka and also completion of 200 years of the arrival of Tamil community of Indian origin in Sri Lanka.

On the 2nd of November 2023, Union Finance Minister Smt. Nirmala Sitharaman participated and graced the 'NAAM 200' organised by the government of Sri Lanka.

Department of Posts is proud to issue a Commemorative Postage Stamp on 200 Years of Indian Origin Tamils in Sri Lanka, recognising the hardships faced by the Indian Origin Tamils and valuing their contribution to the economic development of Sri Lanka.

Credits:

Stamp/FDC/Brochure/ : Smt Nenu Gupta

Cancellation Cachet

Text : Referenced from content provided by
proponent



डाक विभाग Department of Posts

भारतीय मूल के तमिल लोगों के श्रीलंका में 200 वर्ष 200 YEARS OF INDIAN ORIGIN TAMILS IN SRILANKA



विवरणिका BROCHURE

भारतीय मूल के तमिल लोगों के श्रीलंका में 200 वर्ष

श्रीलंका में रह रहे भारतीय मूल के तमिल वास्तव में वे भारतीय तमिल हैं, जिन्हें 'मलयग तमिलर' नाम से भी जाना जाता है। इनमें से अधिकांश 19वीं और 20वीं शताब्दी में कॉफी, चाय तथा रबड़ के बागानों में काम करने के लिए तमिलनाडु से श्रीलंका भेजे गये कामगारों के वंशज हैं। इनका बागान क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये तमिल भाषी लोग अधिकतर मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं।

इस क्षेत्र को मलयगम अथवा पर्वत प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। श्रीलंका (पूर्व में सीलोन) में भारतीय मूल के तमिलों का पहला दल वर्ष 1823 में पहुंचा। ये लोग, वहां के पर्वतीय क्षेत्रों में कॉफी और तत्पश्चात् चाय, रबड़ तथा कोको के बागानों में मजदूरों के रूप में काम करने के लिए आए थे। बाद में 19वीं सदी में भारत से बड़ी संख्या में तमिल लोग सीलोन में वित्तीय क्षेत्र के उद्यमियों और किराना व्यापारियों के रूप में भी बस गए। वे, भारतीय मूल के तमिल लोगों का व्यापारी समूह थे जो पूर्व में सीलोन आ चुके बागान कामगारों अथवा अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं थे। ये लोग बाद में सीलोन आए थे। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अंग्रेजों द्वारा श्रीलंका (तब सीलोन नाम से जाना जाने वाला) का प्रशासन अपने हाथ में ले लिए जाने के बाद, भारतीय मूल के इन तमिल लोगों ने विविध क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसमें आर्थिक जगत के क्षेत्र जैसे बागान और कृषि भी शामिल थे। भारत और श्रीलंका में ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय मूल के तमिलों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 1830 के दशक में, कॉफी एस्टेट में काम करने वाले भारतीय मूल के तमिलों को मजदूरी नहीं दी जाती थी। इसके बजाए, उन्हें उनके द्वारा इकट्ठा किए गए कॉफी बीन्स के बदले दुकानों से सामान खरीदने के लिए कहा जाता था। भारतीय मूल के तमिल लोगों के श्रीलंका प्रवास के लगभग 100 वर्ष बाद अंतरराष्ट्रीय समुदाय को उनकी कठिनाइयों के बारे में पता चला।

वर्ष 1911 की जनगणना में पहली बार श्रीलंका में रह रहे भारतीय तमिलों की एक अलग जातीय समूह के रूप में गणना की गई। उस समय वे श्रीलंका में दूसरा सबसे बड़ा जातीय समूह थे। श्रीलंका सरकार द्वारा उन्हें एक अलग जातीय समूह के रूप में मान्यता दी गई और उस वर्ष के बाद से उन्हें अधिकारिक जनगणना में "भारतीय तमिल" नाम दिया गया। विभिन्न प्रशासकीय और राजनीतिक प्रयोजनों के लिए इस समुदाय को सरकार ने आधिकारिक रूप से "भारतीय तमिल" के रूप में चिह्नित किया।

1940 के दशक में, ट्रेड यूनियन आंदोलन ने बागान मजदूरों को उग्र श्रमिक वर्ग के रूप में तब्दील कर दिया। उन्होंने लंका सम समाज (या समाजवादी) पार्टी (एलएसएसपी) से हाथ मिला लिया, जिसने अधिकतर ब्रिटिश बागान कम्पनियों द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न से मुक्ति के लिए श्रमिक वर्ग द्वारा किए जा रहे संघर्ष को सामने लाया। सीलोन नागरिकता अधिनियम, 1948 ने भारतीय मूल के तमिल समुदाय को नागरिकता से वंचित कर दिया।

चूंकि उन्हें जनप्रतिनिधि चुनकर संसद में भेजने का अधिकार नहीं था, अतः श्रीलंका की संसद ने उन पर ध्यान देना बंद कर दिया। इस प्रकार इन बागान श्रमिकों को वर्ष 1948 से लेकर 1964 तक जैसे भुला ही दिया गया। वे किसी भी प्रगतिशील विधेयक का लाभ नहीं उठा सके। इन बागान श्रमिकों की आवासन, स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की अनदेखी की गई।

वर्ष 1952 में, श्री सौम्यमूर्ति, थॉडामन, अब्दुल अजीज, जी. के. मोथा और पी. पेरीसुंदरम, के. रसलिंगम, सी. आर. मोथा, कोट्टमपल्ली गोविन्दन सेल्लप्पा नायर,

वैथियलिंगम पलनिसामी पिल्लई के नेतृत्व में सीडब्ल्यूसी ने भारतीय मूल के तमिलों को प्रतिनिधित्व से वंचित रखे जाने के विरुद्ध एक सत्याग्रह अभियान की शुरुआत की। इस संघर्ष में अनेक अन्य लोगों ने भी भाग लिया। यह आंदोलन, सीलोन की संसद के बाहर स्थित गाले फेस ग्रीन में हुआ।

भारतीय मूल के तमिलों को नागरिकता से वंचित किए जाने के बाद, कुछेक अधिनियमों के तहत निर्धारित पात्रता मानदंड के अनुसार उन्हें नागरिकता संबंधी अधिकार प्रदान किए गए, जिसके फलस्वरूप वे देश की स्थायी जनसंख्या का हिस्सा बन पाए। यह एक लम्बी प्रक्रिया थी। इस समस्या के समाधान के लिए भारतीय तमिल नेताओं और सत्तासीन लोगों द्वारा राजनीतिक स्तर पर अनेक जोड़-तोड़ किए गए। यह प्रक्रिया भारतीय मूल के तमिलों के लिए अत्यन्त कठिन सिद्ध हुई और इस प्रक्रिया में उन्हें कई बलिदान और वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। श्रीलंका की स्वतंत्रता के बाद उस देश में दो पीढ़ी अथवा उससे भी अधिक समय बिता लेने के बाद, नागरिकता से वंचित भारतीय मूल के 3,00,000 तमिलों को श्रीलंका की संसद में अरुमुगम थॉडामन द्वारा प्रस्तुत विधेयक द्वारा वर्ष 2003 में नागरिकता प्रदान की गई। भारतीय मूल के तमिलों को लंबे समय तक नागरिकता विहीन रहने की व्यथा झेलनी पड़ी। इसका परिणाम यह रहा कि श्रीलंका में रह रहे तमिल लोगों को दो शताब्दियों तक विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ा।

भारत की वर्तमान सरकार ने भारतीय मूल के तमिलों की समस्या का समाधान करने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मई, 2017 में मध्य श्रीलंका, जहां भारतीय मूल के तमिल बसे हैं, का दौरा किया और वहां भारत सरकार की सहायता से पूरी की गई विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में भारतीय मूल के तमिलों के लिए 4000 पक्के मकानों का निर्माण कार्य पूरा किया जाना और 10,000 नए मकानों की घोषणा करना भी शामिल था।

21 जुलाई, 2023 को श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघे के भारत दौरे के दौरान, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने श्रीलंका के साथ राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष और भारतीय मूल के तमिलों के श्रीलंका पहुंचने के 200 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारतीय मूल के तमिलों के लिए 75 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाएं लागू करने की घोषणा की।

2 नवम्बर 2023 को, केंद्रीय वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका सरकार द्वारा आयोजित 'NAAM 200' में भाग लिया।

डाक विभाग, 'भारतीय मूल के तमिलों के श्रीलंका में 200 वर्ष' विषय पर स्मारक डाक-टिकट जारी करते हुए गर्व का अनुभव करता है। साथ ही, भारतीय मूल के तमिलों द्वारा सामना की गई कठिनाइयों को रेखांकित करते हुए श्रीलंका के आर्थिक विकास में उनके योगदान की सराहना करता है।

आभार :

डाक-टिकट/प्रथम दिवस आवरण / : श्रीमती नीनू गुप्ता

विवरणिका/विरूपण कैंसे

पाठ

: प्रस्तावक से प्राप्त सामग्री के आधार पर

तकनीकी आंकड़े

TECHNICAL DATA

मूल्यवर्ग	: 500 पैसे
Denomination	: 500 p
मुद्रितडाक-टिकट	: 301850
Stamps Printed	: 301850
मुद्रण प्रक्रिया	: वेट ऑफसेट
Printing Process	: Wet Offset
मुद्रक	: प्रतिभूति मुद्रणालय, हैदराबाद
Printer	: Security Printing Press, Hyderabad

The philatelic items are available for sale at Philately Bureaus across India and online at http://www.epostoffice.gov.in/PHILATELY_3D.html

© डाक विभाग, भारत सरकार। डाक टिकट, प्रथम दिवस आवरण तथा सूचना विवरणिका के संबंध में सर्वाधिकार विभाग के पास है।

© Department of Posts, Government of India. All rights with respect to the Stamp, First Day Cover and Information Brochure rest with the Department.

मूल्य ₹ 5.00